1	2	3
Heavy Structural Mill	25	17
Merchant Mill	11	7
Refractory	16	12
Energy	73	65
Maintenance	14	12
TOTAL	273	227

Technical Collaboration Agreement Between SAIL and N.K.K. of Japan

3345. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Technical Collaboration Agreement between SAIL and N.K.K. of Japan was signed in June, 1985 for upgradation and Modernisation of technology in the public sector steel plants viz Rourkela Steel Plant, Durgapur Steel Plant and Indian Iron and Steel Co. Ltd.;

(b) what are the terms and conditions financial and otherwise for undertaking such a study by N.K.K.;

(c) what amounts of money has been paid to N.K.K. for this examination and investigation; and

(d) what are the recommendations made by the N.K.K. Japan for improvements of each of these plants and what steps are being taken for its implementation?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The agreement between the Steel Authority of India Ltd. (SAIL) and M/s. N.K.K. of Japan provided for carrying out investigations by the Japanese firm, by putting in 3070 man-days, into key technological areas of SAIL's operations and to make recommendations for technological improvements. It also provided for imparting training to Engineers of SAIL for 1000 man-days. Payments were to be made on the basis of annual retention fee and man-days fee till the end of 1988-89, M/s. N.K.K. have been paid Rs. 11.29 crores.

(d) M/s. N.K.K., after carrying out their studies have so far submitted recommendations covering area like layer charging in blast furnaces, processing of ingots, maintenance and repair standards for shops as well as improved practice in the sinter plant, coke ovens, etc. Most of the recommendations have since been implemented.

धान की नई किस्म

3346. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को खेती के लिये इस वर्ष धान की नई किस्म दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) धान की इस नई किस्म के क्या लाभ हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां, उनका नाम "गोविन्द" तथा "आदित्य" रखा गया है ।

(ख) गर्ष 1989 (जून के अन्त तक) में आम खेती के लिए केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा धान की दो किस्में रिलीज तथा अधिसूचित की गई हैं ।

(ग) ये किस्में पुरानी किस्मों से 10 से 15 प्रतिशत अधिक उपज देने में समर्थ हैं । ये किस्में सूखा, कीटव्याधियों तथा रोगों के प्रति अत्यधिक सहनशील हैं तथा वारानी उपराऊं क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं ।

मध्य प्रदेश मे अनुसूचित जातियों/अनूसचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास

3347. **श्री अजीत जोगी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पिछले तीन वर्षों में कितने नए छात्रावासों को स्वीकृति दी गई ;

(ख) पूरे देश में स्वीकृत किए गए छात्रावासों की तुलना में इसका प्रतिशत कितना है ; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में इन जातियों की जनसंख्या के आधार पर इस संबंध में स्वीकृत किए जाने वले छात्रावासों की संख्या तय कर ली गई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेंद्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को स्वीकृत छात्रावासों की संख्या तथा देशभर में स्वीकृत छात्रावासों की तुलना में उनकी प्रतिशतता निम्नप्रकार है :—

मध्य प्रदेश को स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	देशभर में स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	प्रतिशतता
62	544	11.39

लड़कों के लिए इसी प्रकार की योजना अभी तक नहीं बनाई गई है ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उनसे प्राप्त प्रस्तावों तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों को छात्रावास स्वीकृत किए जाते हैं ।

मध्य प्रदेश को चावल और गेहूं का आवटन

3348. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश को आवंटित किये गए चावल और गेहूं की मात्रा कितनी है और इस राज्य को वास्तव में कितनी मात्रा उपलब्ध करायी गई थी ;

(ख) क्या खाद्यान्नों की यह मात्रा मध्य प्रदेश की कुल आवश्यकता और मांग की तुलना में बहुत कम थी ; और

(ग) इसकी आवश्यकताओं और मांग के अनुसार खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) :(क) और (ख) एक विवरण (उपाबंध) संलग्न है जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में 1988 और 1989 के दौरान सार्वजनिक वितरण